



साप्ताहिक
Live not just breathe

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 22

(प्रति बुधवार), इन्वॉर, 17 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024

पेज : 4

कीमत : 3 रुपये



राम और पर्यावरण

राम के मानवसेवी और पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया है। राम ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जीवन का आदर्श प्रदर्शित किया है और पहाड़ों, नदियों, वनों और प्राकृतिक सुंदरता की महिमा को मान्यता दी है।

डॉ. सोनल मेहता

रामायण के कई प्रमुख पर्यावरण संबंधित प्रसंग शामिल हैं-

1. **राम के वनवास-** राम का 14 वर्ष का वनवास पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की मिसाल है। वनों में जीवन बिताकर, राम और सीता ने प्रकृति की मदद से संघर्ष किया और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का महत्व समझाया।
2. **वानर सेना का सहयोग-** राम के वनवास के दौरान, राम ने वानर सेना का सहयोग ले कर प्रकृति की संरक्षा के लिए संघर्ष किया। वानर सेना ने पेड़-पौधों की रक्षा की और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद की।
3. **हनुमान और प्राकृतिक सुंदरता-** हनुमान, राम के विश्वासपूर्वक भक्त, प्राकृतिक सुंदरता के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पर्वतों को तथा प्राकृतिक आश्रय स्थलों को संरक्षित रखा।
4. **सुंदरकांड-** रामायण के सुंदरकांड में, हनुमान के साहस और प्रियतम वन का सुंदर वर्णन है। यह प्रसंग प्राकृतिक सुंदरता की महिमा और मनुष्य की प्राकृतिक आपूर्ति से जुड़े महत्व को प्रमोट करता है।

राम के जीवन और रामायण के इन प्रसंगों के माध्यम से, हमें प्रकृति की महत्त्वपूर्णता, पारिस्थितिकी, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की महत्वता का आंदाजा होता है। राम का आदर्श प्रदर्शन हमें पर्यावरण स्नेह, बागवानी, जल संरक्षण और प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

रामराज्य और पर्यावरण

संकलनकर्ता

श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव (IAS से.नि.)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के उपरान्त देश में रामराज्य स्थापित करने का सपना देखा था। गांधीजी के इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया गया। रामराज्य की अवधारणा वाल्मीकीय रामायण एवं तुलसीदास कृत रामचरितमानस में है। इस लेख में रामराज्य के पर्यावरण सम्बन्धी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि वानिकी के जिन नवीन सिद्धांतों जैसे- "प्रिन्सिपल ऑफ सस्टेंड यील्ड" आदि को विदेशी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया बताया जाता है कि वे सिद्धान्त रामचरित मानव में पहले से ही मौजूद हैं। रामराज्य की अवधारणा किसी धार्मिक संकीर्णता का द्योतक नहीं है बल्कि यह जनहित कारी अवधारणा है। इस पर गंभीर मनन एवं चिंतन की आवश्यकता है। प्रकृति के सानिध्य के बिना प्रगति की परिकल्पना मरुस्थल में हरियाली के सदृश दिवा स्वप्न है। कंक्रीट के जंगलों से होकर हम भौतिक समृद्धि के कितने ही सोपान पार कर लें, वास्तविक विकास हेतु भावनाओं की जल-धार से ही शुष्क मरुस्थल में हरियाली लाई जा सकती है और तभी चतुर्मुखी विकास सम्भव है। आज हम तथाकथित विकास के एक ऐसे दौर में पहुँच चुके हैं, जहाँ लगातार बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण हमारे अस्तित्व को अनवरत चुनौती दे रहा है। प्रकृति से दूर रहकर किए गए एकांगी विकास का कुपरिणाम हम सब ने भलीभाँति देख लिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मृदा प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, ओजोन परत में छेद एवं अम्लीय वर्षा का अत्यन्त विनाशकारी स्वरूप बुद्धिजीवी एवं विवेकशील व्यक्तियों की चिन्ता का कारण बने हुए हैं। केदारनाथ की भीषण प्राकृतिक आपदा ने मानव समाज को झकझोर दिया है। लम्बे समय तक भौतिक विकास के विनाशकारी मद में मदोन्मत्त लोगों की सुप्त पर्यावरण चेतना अब धीरे-धीरे जागृत हो रही है तथा अब वे भी प्रगति के साथ प्रकृति की बात करने लगे हैं। प्रकृति का सानिध्य, प्रगति का विरोधी नहीं है। प्रकृति और प्रगति के बीच संघर्ष की नहीं, सामन्जस्य की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने

कहा था कि प्रकृति के सहारे हम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, विलासिता की नहीं। विलासिता की वृत्ति किसी भी राष्ट्र अथवा समाज को धीरे-धीरे ऊर्जाहीन कर उसे समाप्त प्राय कर देती है। प्रकृति का सानिध्य भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी ने इस रहस्य को भली-भाँति समझा है। जिस रामराज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी उसकी वैचारिक आधारशिला बहुत पहले महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी द्वारा रखी जा चुकी थी। जब हम अपने किसी मित्र या सम्बन्धी से मिलते हैं तो सभी का हालचाल पूछते हैं किसी से मिलकर हम उसके बच्चों, परिवार आदि की ही कुशलक्षेम पूछते हैं। हम सबने कभी सोचा ही नहीं कि किसी का हालचाल पूछते समय उस क्षेत्र के वनों, नदियों, तालाबों या वन्यजीवों का समाचार जानने की चेष्टा करें। ऐसा इसलिए है कि अब हम वनों, नदियाँ, तालाबों या वन्यजीवों को परिवार का अंग मानते ही नहीं। पहले ऐसा नहीं था। उस समय लोग एक दूसरे का समाचार पूछते समय वनों, बागों, जलस्रोतों आदि की भी कुशलता जानना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उस समय लोग प्रकृति के विभिन्न अवयवों को परिवार की सीमा के अन्तर्गत ही मानते थे। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण चित्रकूट में राम भरत मिलन के समय मिलता है। श्री राम अपने दुखी भाई भरत से पूछते हैं कि उनके दुखी होने का क्या कारण है? क्या उनके राज्य में वन क्षेत्र सुरक्षित हैं? अर्थात् वन क्षेत्रों के सुरक्षित न रहने पर पहले लोग दुखी एवं व्याकुल हो जाया करते थे।

(निरंतर पेज २ पर)

रामराज्य पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न



वाल्मीकि रामायण में वर्णित उदाहरण निम्न प्रकार है-

कच्चिन्नगवनं गुमं कच्चित् ते सन्ति धेनुकाः ।

कच्चिन्न गणिकाश्रानां कुन्जराणां च तृष्यसि ॥ (2/100/50)

जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं, वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हैं न? तुम्हारे पास दूध देने वाली गाएँ तो अधिक संख्या में हैं न? तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? अनेक स्थानों पर वाल्मीकि जी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। श्री भरत जी अपने सेना एवं आयोध्यावासियों को छोड़कर मुनि के आश्रम में इसलिये अकेले जाते हैं कि आस-पास के पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे-

ते वृक्षानुदकं भूमिमाश्रमेषूज्जास्तथा । न हिंस्युरिति तेवाहमेक एवागतस्ततः ॥ (2/91/09)

वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुँचायें, इसलिये मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। पर्यावरण की संवेदनशीलता का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

रामराज्य पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न था। मजबूत जड़ों वाले फल तथा फूलों से लदे वृक्ष पूरे क्षेत्र में फैले हुये थे-

नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः । कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शै मरुतः ॥ (6/128/13)

श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मन्द गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था।

तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि उस समय में पर्यावरण प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। काफी बड़े भू-भाग पर वन क्षेत्र विद्यमान थे। वन क्षेत्रों में ही ऋषियों एवं मुनियों के आश्रम थे, जो उस समय ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र थे। समाज में इन ऋषि-मुनियों का बड़ा सम्मान था। बड़े-बड़े राजा महाराजा भी इन मनीषियों के सम्मान में नतमस्तक हो जाते थे। श्रीराम को वनवास मिलने के उपरान्त सर्वाधिक प्रसन्नता इसी बात की हुई कि वन क्षेत्र में ऋषियों का सत्संग का लाभ प्राप्त होगा- मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहिं भौति हित मोर।

प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान एवं शिक्षा के केन्द्र आबादी से दूर होते थे। प्रकृति की गोद में स्थित इन केन्द्रों से ही हमारी सभ्यता का प्रचार एवं प्रसार हुआ। विभिन्न सामाजिक बुराइयों से ये केन्द्र सर्वथा दूर थे। यहाँ का वातावरण अत्यन्त स्वच्छ एवं निर्मल था। वन एवं वन्य जीवों के प्रति प्रेम यहाँ स्वतः उत्पन्न हो जाता था। ऋषियों एवं मुनियों के प्रत्येक कृत्य से सृष्टि के प्रति प्रेम का सन्देश गूँजता था। मानसिक शान्ति एवं आत्मिक प्रसन्नता यहाँ भरपूर मात्रा में विद्यमान थी तथा विद्याध्ययन करने वाले बच्चों के संस्कार का निर्माण इसी परिवेश में होता था। श्रीराम को आने वाले समय में रामराज्य की स्थापना करनी थी, जिसमें सभी सुखी हो सकें इसलिये स्वाभाविक ही था कि उन्होंने लम्बे समय तक ऋषि-मुनियों के सानिध्य में रहने का निर्णय लिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर वन क्षेत्रों का सजीव वर्णन किया है। वन क्षेत्र घनी आबादी से दूर स्थित होते थे तथा इन क्षेत्रों में भोली-भाली आदिवासी जनता रहती थी। श्री राम ने इन भोले-भाले लोगों से प्रगाढ़ मित्रता स्थापित की और जीवनपर्यन्त उसका निर्वहन किया। निषादराज केवट, वानरराज सुग्रीव एवं गिद्धराज जटायु इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। वनवासी बन्दरों से राम की मित्रता जगत प्रसिद्ध है। इन्हीं बन्दर-भालुओं की सहायता से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की उपेक्षित गिद्ध जटायु को श्रीराम ने अत्यधिक सम्मान दिया। श्रीराम के सानिध्य से अंगद, हनुमान, जामवन्त, नल, नील, सुग्रीव, द्विविद, आदि भालू कपि तथा जटायु जैसे गिद्ध सदा के लिये अमर हो गये। पूरे

रामचरित मानव में हम पाते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को उपभोग मात्र की वस्तु नहीं माना गया है। बल्कि सभी जीवों एवं वनस्पतियों से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित किया गया है। प्रकृति के अवयवों का उपभोग निषिद्ध नहीं है। उनके प्रति कृतज्ञ होकर हम आवश्यकतानुसार उस सीमा तक उपयोग कर सकते हैं जब तक किसी अवयव के अस्तित्व पर संकट न आए। कोई भी प्रजाति किसी भी दशा में लुप्तप्राय नहीं होनी चाहिये। रामराज्य में प्रकृति के उपहार स्वतः प्राप्त थे। तुलसीदास जी ने रामराज्य में वनों की छटा एवं उनसे मिलने वाले उपहारों का चित्रण दर्शनीय है-

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग जग पंचानन ॥
खज मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्दि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥
कूजहिं खग मृग नाना बुंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥
सीतल सुरभि पवन वह मंदा । गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥
लता बिटप माँगे मधु चवहीं । मनभावतो धनु पय स्रवहीं ॥
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भई कृतयुग कै करनी ॥
प्रगटीं गिरिन्ह विविध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥
सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥
सागर निज मरजादा रहहीं । डारहिं रत्न तटन्दि नर लहहीं ॥
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥
बिधु महि पूर मयूखन्दि रवि जप जेतनेहिं काज ॥
मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र के काज । (7/23)

उक्त वर्णन में हम पाते हैं कि प्रकृति रामराज्य में स्वतः उपहार देती थी। वास्तव में प्रकृति हमें सब कुछ देती है हमें केवल धैर्य एवं विवेक से रहना है। प्रकृति का सीमित विदोहन ही सुखमय भविष्य की गारंटी है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु का उपभोग हमें प्रकृति से छेड़छाड़ किये बिना करना चाहिये। गणितीय भाषा में यदि हम केवल ब्याज का उपभोग करें, तो मूलधन सदा बना रहेगा एवं हम ब्याज का सदैव उपभोग करते रहें। विदोहन का यही नियम कल्याणकारी है। रामराज्य में प्रकृति का विदोहन निषिद्ध है। प्रकृति का असीमित विदोहन अपराध है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति प्रदत्त उपहारों का उपभोग ही रामराज्य का आदर्श है। आधुनिक वानिकी का निरन्तर उत्पादन का सिद्धान्त भी इसी प्रकार का है-

रामराज्य में उक्त परिकल्पना से भी सुन्दर स्थिति की कल्पना की गयी है। प्रकृति द्वारा स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से प्रदत्त उपहारों का प्रकृति के प्रति आत्मीयता या कृतज्ञता रखते हुये उपभोग करना ही रामराज्य का आदर्श है। आधुनिक वानिकी के सततता के सिद्धान्त का यही तात्पर्य है कि हम वानिकी उत्पादों का उपभोग इस प्रकार करें कि मूल सम्पत्ति को कोई क्षति न पहुँचे। हमारे पूर्वजों की सोच इससे भी कहीं आगे थी। वन क्षेत्रों को क्षति न पहुँचे, इतना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वन क्षेत्रों में सतत वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिये। इसीलिये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न होते हुये भी दशरथ, राम, सीता एवं लक्ष्मण द्वारा समय-समय पर पौध रोपण कार्य किया गया है। सृष्टि का प्रत्येक अवयव, जिसका निर्माण कृत्रिम विधियों से नहीं किया जा सकता, हमारे लिये अमूल्य है। प्रकृति के किसी भी अंग की उपेक्षा करके हम सुखी नहीं रह सकते। स्वस्थ एवं समृद्ध पर्यावरण के बिना रामराज्य की स्थापना सम्भव नहीं है। जीवन की प्रथम आवश्यकता है- शुद्ध वायु। रामराज्य में वायु पूर्णतः शुद्ध थी-

सीतल सुरभि पवन बह मंदा। प्रदूषित वायु धरती पर जीवन के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है, धीरे-धीरे यह तथ्य अब प्रबुद्ध लोगों के समझ में आ रहा है। रामराज्य वन क्षेत्रों से भरा था। सभी वृक्ष हरे-भरे पुष्प तथा फल सम्पन्न थे। समृद्ध वन में वन्यजन्तु स्वाभाविक रूप से रहा करते थे। सभी वन्यजीव ऐसे वन क्षेत्र में प्रफुल्लित थे। शेर, हाथी, विविध प्रकार के रंग-बिरंगे पक्षी तथा विभिन्न प्रजातियों के हिरण आदि जीवन को जीवन्त बनाया करते थे। रामराज्य में सभी जीव-जन्तु प्रसन्न मन से अपना स्वाभाविक जीवन जीते थे। प्रकृति के किसी भी अवयव से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। वन क्षेत्रों की कमी से ईंधन एवं चारा की विकट समस्या उत्पन्न होती है। ग्रामीण क्षेत्र ईंधन एवं चारा की कमी से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। चारे की कमी से दूध-दही का उत्पादन घटता है जो मानव जीवन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। रामराज्य में ईंधन एवं चारा की कमी नहीं थी इसलिये गाय पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी- मनभावतो धेनु स्रवहीं। यही कारण है कि रामराज्य में सभी स्वस्थ एवं निरोग थे। जीवन की द्वितीय मूल आवश्यकता है- शुद्ध पेयजल। रामराज्य में सभी नदियाँ शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण थीं- सरिता सकल बहहिं बर बारी। सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ सभी तालाब गहरे जल से भरे थे जिसमें कमल के पुष्प खिले रहते थे। शुद्ध वायु एवं पेयजल की उपलब्धता किसी भी सभ्यता के विकास का केन्द्र बिन्दु है। इसके बिना विकास की कोई भी अवधारणा दिवास्वप्न है। वायु एवं पेयजल के प्रदूषण से हम आज जूझ रहे हैं। हमने सभी नदियों को लगातार प्रदूषित किया है। यदि हम रामराज्य के अभिलाषी हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की अवधारणा के अनुरूप शुद्ध पेयजल एवं शुद्ध वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही होगा। ऐसा कोई भी कार्य हमें प्रत्येक दशा में बन्द करना होगा जो वायु एवं जल को प्रदूषित करता हो चाहे उससे कितना भी भौतिक लाभ मिलता हो। पर्यावरण प्रदूषण का मूल कारण है हमारी लिप्सा। धरती मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम है। किन्तु लगातार अनियन्त्रित रूप से बढ़ रही भोगवृत्ति स्वयं धरती को बर्बाद करती है। खनिज, धातु, पेट्रोल, डीजल आदि सभी हमें धरती माँ की कोख से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा किये जा रहे असीमित विदोहन से धरती लगातार ऊसर एवं बंजर होती जा रही है। हम यह भी नहीं सोच पा रहे हैं कि असीमित विदोहन जारी रहने से मानव की आने वाली सन्तति का भविष्य क्या होगा? रामराज्य में विदोहन की वृत्ति नहीं थी। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वाभाविक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों एवं समुद्री क्षेत्र से हो जाया करती थी। धरती हरी-भरी थी। पर्याप्त वन क्षेत्र विद्यमान थे। कृषक सम्पन्न थे। किसानों की सम्पन्नता से राज्य समृद्ध था। अभाव का नामोनिशान न था। आवश्यकता से अधिक पर्यावरण प्रदूषण मौसम को परिवर्तित कर देता है। समय पर वर्षा न होना, अत्यधिक वर्षा का होना, अम्लीय वर्षा आदि का कुप्रभाव आज हम देख रहे हैं। कृषि प्रधान देश के लिये यह स्थिति विनाशकारी है। रामराज्य में बादलों से आवश्यकतानुसार ही वर्षा होती थी। कुछ लोगों को यह अतिशयोक्ति लग सकता है। किन्तु स्वस्थ पर्यावरण में सर्दी, गर्मी और वर्षा नियमित रहती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुलसीदास जी अत्यन्त दूरदर्शी थे। आज जिन समुद्री तूफानों का कुपरिणाम हमें अभिशाप कर रहा है, उसकी कल्पना उन्हें थी। सुनामी का कहर अनेक परिवारों को समाप्त कर चुका है। यह सब पर्यावरण प्रदूषण का ही कुप्रभाव है। रामराज्य में समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे। ऐसा तभी सम्भव है जब पूरा मानव समाज पर्यावरण संरक्षण के प्रति पर्याप्त संवेदनशील हो।

सिंहस्थ 2028 से पहले क्षिप्रा नदी की शुद्धि के लिये कार्य योजना तैयार करें- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सिंहस्थ की प्लानिंग में साधु-संतों का परामर्श लें

कान्ह नदी के गंदे पानी को रोकने की सुविचारित प्लानिंग करें

भोपाल(एजेंसी)मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के मददेनजर क्षिप्रा नदी का पानी स्वच्छ निर्मल एवं आचमन योग्य बनाने के लिये इंदौर, उज्जैन एवं देवास के संबंधित अधिकारियों को क्षिप्रा नदी को साफ रखने की कार्य योजना तैयार करें। गंदे पानी को रोकने के लिए जगह-जगह स्टॉप डैम बनाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य एवं क्षिप्रा शुद्धिकरण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने इंदौर एवं उज्जैन संभाग के संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को कार्ययोजनाएं बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर महाकाल लोक फेस-3 के कार्यों की भी शुरुआत की जायेगी। उन्होंने क्षिप्रा के उद्गम से लेकर समाप्ति स्थल तक घाटों पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की विस्तृत कार्ययोजनाएं बनाने का निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश का सबसे बड़ा कुंभ मेला सिंहस्थ 12 वर्ष में एक बार उज्जैन में आयोजित होता है जब सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं। मेले में साधु, संत, महामंडलेश्वर, गणमान्य नागरिक एवं आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। सिंहस्थ का आयोजन न केवल उज्जैन बल्कि देश के लिए एक गौरवशाली क्षण होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के अलावा सिंहस्थ मेले का इंदौर, देवास, ओंकारेश्वर दादा धुनी वाले, पशुपतिनाथ मंदिर, बगलामुखी मंदिर में भी सिंहस्थ मेले का विस्तार रहता है। सभी जगह आम जनता की सहभागिता रहती है। जब श्रद्धालु आए तो मेले में गौरव का अनुभव करें। सिंहस्थ 2028 की प्लानिंग साधु संतों की सलाह पर करने और उनके परामर्श से ही कार्ययोजनाएं बनाने के निर्देश



दिये। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कान्ह नदी का गंदा पानी क्षिप्रा में रोकने के लिए बनाई गई 99 करोड़ रुपए की डायवर्जन प्लानिंग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार में ही ऐसी योजना बनायें कि क्षिप्रा का जल पीने और आचमन योग्य बन जाए। गलत प्लानिंग के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार से क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए आवश्यक बजट की मांग की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी सिंहस्थ मेला गौरवशाली सनातन परंपरा के अनुसार आयोजित किया जायेगा। इसके लिए क्षिप्रा नदी शुद्धिकरण के साथ ही उज्जैन के महाकाल मंदिर तक जाने के लिए सड़क मार्ग चौड़ीकरण, मंदिर तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की प्लानिंग, पावर स्टेशन,

हवाई पट्टी विस्तार, संग्रहालय, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग आदि के भी विकास कार्य पूरा किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ प्रबंधन के लिए भी वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन पार्किंग एवं शुद्ध पेयजल तथा ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी की जाएगी।

सिंहस्थ 2028 में 12 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान बताया गया कि सिंहस्थ 2028 में 12 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान है। इसके लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाएगी। इंदौर में क्षिप्रा नदी में नालो का गंदा पानी रोकने के लिए 9 स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 9 स्टाप डैम वहां-वहां बनाए जाएंगे जहां-जहां गंदे नाले का पानी क्षिप्रा में मिल रहा है। विभिन्न देवस्थानों, वाल्मीकि घाट, सिद्धवट, काल भैरव, सिद्धनाथ आदि के घाटों का भी विस्तार होगा। जहां-जहां संत रहते हैं उन घाटों का विस्तार प्राथमिकता से किया जाएगा, एवं मेला क्षेत्र में भी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल मंदिर के अलावा राम जनार्दन मंदिर, सिद्धनाथ, काल भैरव जहां सेटलाइट टावर है, वहां भी भीड़

को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक प्लान बनाए जाएंगे। डॉ यादव ने कहा की एक ही सड़क पर भीड़ का भार डालना उचित नहीं है, इसके लिए चार से पांच वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जाएंगे। उन्होंने प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण करने, हरि फाटक ब्रिज के चौड़ीकरण, के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बियाबानी चौराहा से बीमा अस्पताल, अस्पताल से कोयला फाटक तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी हो। एम आर से बड़े पुल

तक सड़क कनेक्टिविटी हो। इसके अलावा ढाबा रोड का भी चौड़ीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केडी गेट से निकास चौराहे तक के पहले से चल रहे रूटीन कार्य होते रहे। विभिन्न धर्मों के लोग यदि उज्जैन में धर्मशाला बनाना चाहते हैं तो उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अच्छे घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं के स्नान की भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी कार्य योजना में कोई चूक नहीं होनी चाहिए सभी योजनाएं शत प्रतिशत सफल होनी चाहिए। उन्होंने पार्वती काली सिंध नदी लिंक योजना पर निर्णय लिया जायेगा। बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, संभागायुक्त इंदौर श्री माल सिंह, संभागायुक्त उज्जैन डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर इंदौर श्री आशीष सिंह, कलेक्टर उज्जैन श्री नीरज सिंह, कलेक्टर देवास श्री ऋषभ गुप्ता, नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।

भारत में खेती से बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सरकार ने माना

भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कृषि दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हालांकि 2016 से 2019 तक कुल उत्सर्जन में कृषि की हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत से घटकर 13.4 प्रतिशत हुई है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र से होने वाला पूर्ण उत्सर्जन 3.2 प्रतिशत बढ़ गया, जो 421 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष तक पहुंच गया। कृषि के कारण कुल उत्सर्जन 4.5 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 2,647 स्क्वियर टन हो गया, जो 2016 में 2,531 था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सौंपे गए तीसरे नेशनल काम्युनिकेशन एंड इनिशियल एडप्टेशन कॉम्युनिकेशन में इसकी सूचना दी गई है। कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का स्रोत पशुधन की वजह से होने वाले मीथेन से उत्पन्न होता है, जो मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों में पाचन प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है। इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के स्रोत चावल की खेती और कृषि मिट्टी से उत्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड हैं। सामूहिक रूप से, ये स्रोत कुल कृषि उत्सर्जन में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। कृषि अवशेषों को खेत में जलाने से भी अतिरिक्त उत्सर्जन होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने प्रदान किया स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023

भोपाल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में वर्ष 2023 का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर शहर को प्रदान किया। गार्बेज फ्री शहर में 7-स्टार रेटिंग के साथ इंदौर ने लगातार सातवीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान का पुरस्कार भी मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में टीम मध्यप्रदेश ने पुरस्कार ग्रहण किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों और स्वच्छता मित्रों को बधाई देते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर का लगातार सातवीं बार स्वच्छता के शिखर पर पहुंचने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन को जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश स्वच्छता के संकल्प को साकार करने में निरंतर अपना योगदान देता रहेगा और आशा व्यक्त कि की आगामी सर्वेक्षण में प्रदेश और बेहतर प्रदर्शन करेगा। प्रदेश में स्वच्छता के प्रयासों से 7 शहरों को वाटर प्लस, 361 शहरों को ओडीएफ++,



3 शहरों को ओडीएफ+ और 7 शहरों को ओडीएफ दर्जा प्राप्त है। प्रदेश में एक 7-स्टार, एक 5-स्टार, 24 3-स्टार और 132 1-स्टार गार्बेज फ्री शहर हैं। कार्यक्रम में भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों की सूची में गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग के साथ पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी को पश्चिम जोन के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में नौरोजाबाद और अमरकंटक को फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है। महु ने सबसे स्वच्छ कैटेगरी में बोर्ड का खिताब हासिल किया है।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकनिज्म एक अवसर!

कार्बन सघन उद्योगों मसलन स्टील, सीमेंट और उर्वरक आदि में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में हो रहे परिवर्तन में भी इसे महसूस किया जा सकता है। वर्ष 2023 के मध्य में जब से यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकनिज्म (सीबीएएम) की घोषणा की, तब से भारतीय उद्योग जगत ने खुलकर इसके प्रति अपने पूर्वग्रह जताए। यह व्यवस्था आयात पर उत्सर्जन शुल्क लगाती है। सलाहकार सेवा प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और कारोबारी संचालन यानी ईएसजी में कर पारदर्शिता को लेकर हुए एक हालिया सर्वेक्षण में 67 फीसदी प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि सीबीएएम उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकता है। ये आशंकाएं गलत नहीं हैं। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एनर्जी, एन्वायरनमेंट एंड वाटर ने अनुमान लगाया है कि इससे कर लागत बढ़ने और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ने से यूरोपीय संघ को होने वाले 43 फीसदी भारतीय निर्यात प्रभावित होगा। यूरोपीय संघ हमारा दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। उदाहरण के लिए इस्पात क्षेत्र में भारतीय मिलों का कार्बन उत्सर्जन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक है। इसलिए कुछ अनुमानों के मुताबिक सीबीएएम व्यवस्था में इसकी कीमत 56 फीसदी तक बढ़ सकती है। कार्बन बॉर्डर टैक्स जनवरी 2026 से लागू होगा। यह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55 फीसदी कमी करने के लक्ष्य का हिस्सा है। परंतु भारतीय निर्यातकों को पहले से ही जटिल अनुपालन चुनौतियों का अंदाजा हो गया है। ऐसा अक्टूबर 2023 में यूरोपीय संघ के साथ उत्सर्जन डेटा साझा करने के लिए सात कार्बन सघन क्षेत्रों की कंपनियों की अनिवार्य परीक्षण अवधि की शुरुआत के साथ ही हो गया। अधिकांश भारतीय कंपनियां सीबीएएम को एक संरक्षणवादी उपाय मानती हैं और इसकी वजह भी है।

भारत सरकार बहुपक्षीय मंचों पर इसके खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है। यह अपील 'साझा किंतु विभेदित जवाबदेही' के सिद्धांत के तहत की जा सकती है। टीकाकारों ने भी सुझाया है कि भारतीय कंपनियां अपने निर्यात बाजार में विविधता लाएं और उन देशों को निर्यात बढ़ाएं जहां उत्सर्जन के मानक इतने सख्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को निर्यात बढ़ाया जा सकता है। ये उचित और आवश्यक प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन इनमें समय लग सकता है। परंतु वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं और इस कवायद की जरूरत को देखते हुए भारतीय उत्पादकों के लिए बेहतर यही होगा कि वे अधिक सक्रियता दिखाते हुए सीबीएएम की चुनौती से पार पाने के तरीके तलाशने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर सीबीएएम के लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि यूरोपीय संघ ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बदलाव आए। पीडब्ल्यूसी का अध्ययन दिखाता है कि अधिकांश कंपनियां इस बात को समझती हैं कि शुरुआती बदलाव में जोखिम कम करने के अवसर निहित हैं। सर्वे में शामिल आधी कंपनियों ने कहा कि उनकी विशुद्ध शून्य की प्रतिबद्धता है और वे सक्रिय ढंग से ऐसे तरीके तलाश कर रही हैं ताकि उन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इनमें से करीब आधी कंपनियों ने 2030 तक विशुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। कार्बन सघन उद्योगों मसलन स्टील, सीमेंट और उर्वरक आदि में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में हो रहे परिवर्तन में भी इसे महसूस किया जा सकता है। आंशिक तौर पर ऐसा राज्य के स्वामित्व वाली ग्रिड बिजली आपूर्ति की संरचनात्मक कमी को दूर करने के लिए तथा आंशिक तौर पर कम लागत वाले ईएसजी फंड तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है। अन्य कंपनियां हरित हाइड्रोजन तकनीक का परीक्षण कर रही हैं। इस बदलाव का तात्कालिक परिणाम ऊंची लागत के रूप में सामने आ सकता है लेकिन दीर्घावधि में भारतीय उद्योग जगत के पास यह अवसर है कि वह अधिक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आए। देश का हालिया औद्योगिक इतिहास दिखाता है कि कंपनियों को ऐसी चुनौतियों से लाभ हुआ है।

अब 1.32 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया जुर्माना

झाबुआ. पहले ही तंगहाली के दौर से गुजर रही झाबुआ नगर पालिका पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसकी वजह नदियों में गंदा पानी मिलने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाना बताई जा रही है। जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। झाबुआ नगर पालिका की माली हालत पहले ही खराब है। अक्टूबर माह से ही कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। दूसरी तरफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश ने मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। झाबुआ नपा के हर महीने का औसत खर्च ही करीब एक करोड़ रुपए हैं और सारे संसाधनों से समय 35 से 40 लाख रुपए से ज्यादा की आई नहीं हो पा रही। इसलिए नपा आर्थिक संकट से जूझ रही है। पेयजल योजना के लिए जो 47 करोड़ का कर्ज लिया था उसके लिए हर तीसरे माह 27 लाख 10 हजार रुडको को किस्त देने पडती हैं। बैराज निर्माण में डूब प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए 2 करोड़ 70 लाख का कर्ज लिया था इसके लिए 4 लाख अदा किए जाते हैं।